संक्षेप में

नैटको फार्मा का लाभ 40 फीसदी टूटा

सितंबर 2019 में समाप्त तिमाही में नैटको फार्मा लिमिटेड का कर पूर्व एकीकृत लाभ 40 फीसदी की गिरावट के साथ 139.4 करोड़ ररुपये रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 235.3 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही में कंपनी की कुल आय 11 फीसदी घटकर 518.9 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 583.5 करोड़ रुपये रही थी। कंपनी ने कहा कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले राजस्व व लाभ में गिरावट अमेरिका में ओस्टेलामिविर की बिक्री और भारत में हेप सी की बिक्री में संभावित गिरावट के कारण दर्ज हुई। कंपनी के निदेशक मंडल ने 2 रुपये वाले हर शेयर के लिए एक रुपये के अंतरिम लाभांश की सिफारिश की है। *बीएस*

सीजी पावर ने 3,300 करोड़ रु. लौटाने को कहा

धोखाधड़ी का शिकार बनी सीजी पावर ऐंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने प्रवर्तक गौतम थापर से जुड़ी कंपनियों और अन्य से 3,300 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है। इसके साथ ही कंपनी ने कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन की दूसरे चरण की जांच शुरू की है ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके। सीजी पावर ने अगस्त में कहा था कि उसके बोर्ड द्वारा अगस्त में की गई जांच में कंपनी के संचालन और वित्तीय लेनदेन में खामियां दिखी थीं। *भाषा*

टाटा मोटर्स को रकम की दरकार!

संभावित साझेदारी के लिए बीएमडब्ल्यू और गीली से बातचीत कर रही कंपनी : ब्लूमबर्ग

कृष्णकांत और शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 12 नवंबर

टाटा मोटर्स को अपने लक्जरी कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) और घरेलू वाहन कारोबार की घटती लाभप्रदता के मद्देनजर मूल कंपनी अथवा किसी संभावित संयुक्त उद्यम साझेदार से ताजा इक्विटी निवेश जुटाने की जरूरत है। इससे उसे अपने बहीखाते की मजबूती को बकरार रखने में मदद मिलेगी।

ब्लूमबर्ग की खबर के अनुसार, टाटा समूह की इस प्रमुख कंपनी ने जेएलआर के लिए साझेदारी की संभावनाएं तलाशने के लिए कार विनिर्माताओं से संपर्क किया है जिसमें चीन की कंपनी झेजियांग गीली होल्डिंग ग्रुप और बीएमडब्ल्यू एजी शामिल हैं। ब्लूमबर्ग ने इस मामले से अवगत सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। टाटा मोटर्स के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी बाजार के कयासों पर टिप्पणी नहीं करती है।

टाटा मोटर्स का समेकित सकल लीवरेज अनुपात इसी साल सितंबर के अंत में 1.83 गुना हो गया जो पिछले नौ वर्षों का सर्वोच्च स्तर है। पिछले 18 महीनों के दौरान जेएलआर और घरेलू कारोबार में नुकसान के कारण शुद्ध हैसियत अथवा शेयरधारकों की इक्विटी को तगड़ा झटका लगा। मार्च 2018 के अंत में कंपनी का लीवरेज अनुपात 0.8 गुना रहा था।

वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही के दौरान समेकित आधार पर कंपनी की शुद्ध हैसियत में एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 45 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। जबकि समान अवधि में उसकी कुल उधारी पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 3 फीसदी बढ़ गई।

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान टाटा मोटर्स ने 3,914 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया। जबकि मार्च 2019 में समाप्त पिछले छह महीनों के दौरान उसका शुद्ध घाटा करीब 2,600 करोड़ रुपये रहा था। सितंबर 2019 में समाप्त छमाही के दौरान कंपनी को करीब 3,000 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान कंपनी का घरेलू कारोबार भी घाटे में चली गई और उसने 1,379 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया।

इन सब घाटों से कंपनी के संचित मुनाफे को झटका लगा। इससे कंपनी की शुद्ध हैसियत में गिरावट आई और उसका डेट बनाम इक्विटी अनुपात बढ़ गया। विश्लेषकों का कहना है कि कंपनी का मौजूदा डेट बनाम इक्विटी अनुपात काफी अधिक है और इससे उसकी उधारी लागत बढ़ सकती है। ऐसे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कंपनी की रेटिंग भी घटा सकती हैं।

एक विश्लेषक ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि वाहन एवं विनिर्माण जैसे चक्रिय कारोबार में डेट बनाम इक्विटी अनुपात 1.0 से अधिक होने पर कंपनी को चिंताजनक स्थिति में माना जाता है। इससे कंपनी के मूल्यांकन और रकम जुटाने की क्षमता प्रभावित होती है।

समेकित शुद्ध हैसियत एवं लीवरेज अनुपात *(छमाही आधार पर)*

छमाही	शुद्ध हैसियत (करोड़ रुपये में)	डेट-इक्विटी अनुपात (आरएचएस)*	छमाही	शुद्ध हैसियत (करोड़ रुपये में)	डेट-इक्विटी अनुपात (आरएचएस)*
सितंबर 2012	40,353.1	1.0	सितंबर 2016	54,698.7	1.3
मार्च 2013	37,637.3	1.2	मार्च 2017	58,061.9	1.3
सितंबर 2013	55,256.3	1.0	सितंबर 2017	79,074.7	1.0
मार्च 2014	65,603.5	0.8	मार्च 2018	95,427.9	0.8
सितंबर 2014	67,831.1	0.9	सितंबर 2018	95,089.3	1.0
मार्च 2015	56,261.9	1.2	मार्च 2019	60,179.6	1.5
सितंबर 2015	80,945.3	0.8	सितंबर 2019	52,254.1	1.8
मार्च 2016	78,952.4	0.8			

*सकल आधार पर (बहीखाते पर नकदी एवं समतुल्य को छोड़कर)
स्रोतः कैपिटालाइन

टीसीएस ने फीनिक्स ग्रुप संग बढ़ाई साझेदारी

रोमिता मजूमदार
मुंबई, 12 नवंबर

फीनिक्स ग्रुप के साथ ब्रिटेन में अपने बीएफएसआई प्लेटफॉर्म में विस्तार के लिए एडिनबर्ग में एक परिचालन केंद्र स्थापित करेगी टीसीएस

प्रमुख आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने फीनिक्स ग्रुप के साथ अपने दीर्घावधि साझेदारी में विस्तार की घोषणा की है। इससे कंपनी को वृद्धि को रफ्तार देने और स्टैंडर्ड लाइफ कारोबार में बदलाव करने और उसके ग्राहकों एवं सलाहकारों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। टीसीएस इस सौदे के बाद एडिनबर्ग परिचालन सेवा केंद्र के जरिये स्कॉटलैंड में अपनी मौजूदगी भी बढ़ाएगी।

दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी में विस्तार से टीसीएस बीएफएसआई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टैंडर्ड लाइफ के पेंशन एवं बचत कारोबार में डिजिटल बदलाव करने में मदद मिलेगी। इससे कुल मिलाकर 42 लाख बीमाधारकों के लिए संभावनाओं में विस्तार होगा। ब्रिटेन में टीसीएस की सहायक इकाई डिलिजेंटा फीनिक्स ग्रुप के बदले करीब 1 करोड़ बीमाओं का प्रबंधन करती है।

टीसीएस के अध्यक्ष (बीएफएसआई प्लेटफॉर्म) सुरेश मुत्तुस्वामी ने कहा, 'हम सक्रिय पॉलिसी के साथ-साथ उन नई पॉलिसियों के लिए भी सेवाएं देंगे जिन्हें बाजार में आना अभी बाकी है। वे सभी योजनाएं हमारे प्रमुख सॉफ्टवेयर टीसीएस बीएएनसीएस पर केंद्रित होंगी।' उन्होंने कहा, 'इस साझेदारी से हमारी ओपन बुक दक्षता में उल्लेखनीय विस्तार होगा और हमारा अनुभव कहीं अधिक बढ़ेगा।'

कंपनी ने इस दीर्घावधि साझेदारी के समयावधि और वित्तीय खुलासे नहीं किए हैं। पिछले साल टीसीएस ने फीनिक्स ग्रुप के साथ 12 वर्षों की अपनी साझेदारी में विस्तार किया था।

टाटा स्टील ने वाहन क्षेत्र में नरमी को दी मात

जयजित दास
भुवनेश्वर, 12 नवंबर

टाटा स्टील औद्योगिक परियोजना और ब्रांडेड उत्पाद जैसी श्रेणियों में अधिक बिक्री दर्ज करते हुए वाहन क्षेत्र में जारी नरमी को मात देने में सफल रही है। वित्त वर्ष 2020 के अप्रैल से सितंबर के दौरान टाटा स्टील ने औद्योगिक उत्पादों और परियोजनाओं की मात्रात्मक बिक्री में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की।

जबकि ब्रांडेड उत्पाद और खुदरा श्रेणी की बिक्री में 10 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। समीक्षाधीन अवधि में कंपनी के कच्चे इस्पात के उत्पादन में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई जबकि डिलिवरी 6 फीसदी बढ़कर 81 लाख टन हो गई।

टाटा स्टील ने एक निवेशक प्रस्तुति में कहा है, 'मंदी के बावजूद ब्रांडेड उत्पाद एवं खुदरा श्रेणी और औद्योगिक उत्पाद एवं परियोजना श्रेणी में डिलिवरी काफी हद तक अच्छी रही। ऑटोमोटिव श्रेणी में कमजोर बिक्री की भरपाई अधिक निर्यात के जरिये की गई।'

टाटा स्टील सूक्ष्म केंद्रित श्रेणियों में अपनी मौजूदगी बेहतर करते हुए और चैनल विस्तार के जरिये ब्रांडेड उत्पादों की कहीं अधिक बिक्री कर सकती थी। 'आशियाना' व्यक्तिगत मकान बनाने वालों के लिए कंपनी का पहला मल्टीब्रांड पोर्टल है जहां टाटा स्टील के छह ब्रांड मौजूद हैं। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से सितंबर की अवधि में आशियाना ने 100 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जबकि पूरे वित्त वर्ष 2019 के दौरान उसे 100 करोड़ रुपये की आय हुई थी। कंपनी वित्त वर्ष 2020 के अंत तक आशियाना से 250 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने की ओर अग्रसर है। टाटा समूह की इस्पात विनिर्माता कंपनी ने एलपीजी श्रेणी में तिमाही दर तिमाही अपना प्रदर्शन सुधारा है।

प्रपत्र — 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	रैडटोपाज़ रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	24/03/2006
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45201DL2006PTC147961
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय** (एमसीए डेटा के अनुसार) गोपी राम बिल्डिंग, खसरा नं. 300, सुल्तानपुर गाँव नई दिल्ली – 110030
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	23/08/2019 (आदेश IRP द्वारा दिनांक 28/08/2019 को प्राप्त हुआ)
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	13/11/2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता :	यह जानकारी **vikasgarg_k@rediffmail.com** पर ई मेल भेजकर मांगी जा सकती है
9.	धारा 29ए के अधीन लागू अग्राह्यता के मानदंड :	यह जानकारी **vikasgarg_k@rediffmail.com** पर ई मेल भेजकर मांगी जा सकती है
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	28/11/2019
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	08/12/2019
12.	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	13/12/2019
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	23/12/2019
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	13/12/2019
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	योग्य संभावित आवेदकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साझा किया जाएगा
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	15/01/2020
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	समाधान प्लान, समाधान पेशेवर को रजिस्टर्ड पोस्ट / व्यक्तिगत सुपर्दगी द्वारा सीलबंद लिफाफे में तथा डिजिटल कॉपी पैन–ड्राइव में क्रमांक 21 पर दिए गए पते पर भेजें।
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	04/02/2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**सीएस विकास कुमार गर्ग** समाधान पेशेवर रैडटोपाज़ रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड **पंजीकरण संख्या** : IBBI/IPA-002/IP-N00738/2018-2019/12291
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	डी–4 बी, प्रथम तल, रामप्रस्थ, रघुनाथ मंदिर के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201011 **ई–मेल :** vikasgarg_k@rediffmail.com
21.	पता और ई–मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	डी–4 बी, प्रथम तल, रामप्रस्थ, रघुनाथ मंदिर के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201011 **ई–मेल :** vikasgarg_k@rediffmail.com vikasgarg_k@outlook.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	विवरण क्रमांक 21 में दिए मेल पर अनुरोध भेजकर उपलब्ध कराया जा सकता है / कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट www.redtopazcirp.com पर भी उपलब्ध है।
23.	प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि	**13/11/2019**

हस्ता / –
सीएस विकास कुमार गर्ग
समाधान पेशेवर
रैडटोपाज़ रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के लिए
पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00738/2018-2019/12291
डी–4 बी, प्रथम तल, रामप्रस्थ, रघुनाथ मंदिर के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201011

तिथि : 13 / 11 / 2019
स्थान : गाजियाबाद

भारतीय खाद्य निगम FOOD CORPORATION OF INDIA
हैडक्वार्टर्स, नई दिल्ली-110001
FUNDS DIVISION

अल्पावधि ऋण हेतु आमंत्रण का प्रस्ताव
भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक माह की समयावधि हेतु अनुसूचित बैंकों से अल्पावधि ऋण के माध्यम से रु. 10000 करोड़ की राशि ग्रीन शू आप्शन के साथ उधार लेने हेतु विचार किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** और **http://fci.gov.in/tender.php** देखें। प्रस्ताव जमा करने की **अंतिम तिथि 28.11.2019** को **अपराह्न 11:00 बजे** तक है। **महाप्रबंधक (निधि)**
टेली फैक्स 011–43527407

एअर इंडिया AIR INDIA
A STAR ALLIANCE MEMBER

निविदा आमंत्रण सूचना

एअर इंडिया लिमिटेड **आरएफएक्स नं. 5000001750** के तहत उड़ान में उपयोग हेतु **'बोन चाईना क्रॉकरी'** की आपूर्ति के लिए **केवल निर्माताओं से बिड्स** आमंत्रित करती है।

निविदा की अंतिम तिथि 03.12.2019 को 1600 बजे तक है।

भावी बिडर्स निविदा की समाप्ति तक जारी किसी भी संशोधन के लिए नियमित रूप से एअर इंडिया वेबसाइट देखते रहें। अन्य जानकारी के लिए दस्तावेज **www.airindia.in** से डाउनलोड किए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, आप **26265838** पर सम्पर्क कर सकते हैं / ईमेल : **AS.Kanthe@airindia.in**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
शाखा:- गोखले मार्केट दिल्ली-110054
फोन:011-23910914 ई-मेल:bo0613@pnb.co.in

कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति के लिए नियम 8 (1) देखे

यत:(Whereas) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत एंव धारा 13(12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोखले मार्केट दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते एक डिमाण्ड नोटिस दिनांक 13.02.2019 को जारी किया गया, जिसके द्वारा ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार मैसर्स अमन सैल्स कॉरपोरेशन (प्रो. श्री अज्ञा पाल सिंह)34 शंकर मार्केट के सामने गोखले मार्केट तीस हजारी दिल्ली-110054, श्री अज्ञा पाल सिंह 34 शंकर मार्केट के सामने गोखले मार्केट तीस हजारी दिल्ली-110054, श्रीमती रवजीत कोर (जमानतदार) के- 6, तिसरी मंजिल, नवीन शाहदरा दिल्ली-110092 को नोटिस मे उल्लेखित राशि रूपये 42,47,087/- (रूपये बयालीस लाख सेतालीस हजार सतयासी रूपये मात्र) 13.02.2019 तक जिसके साथ भविष्य का ब्याज दिनांक 01.01.2019 से प्रभवी एंव कानूनी प्रभार और अन्य खर्चे का भुगतान इस नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिन के भीतर, करने के लिये कहा गया था।

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान करने में असफल हो जाने पर ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्यता एतत् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 08.11.2019 को उक्त अधिनियम कि धारा 13 (4) सपठित उक्त नियमावली के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेष रूप से तथा जनसमान्य को समान्य रूप से तक सावधान किया जाता है इस सम्पत्ति बाबत् कोई संव्यवहार नही करे और इस सम्पत्ति के बाबत् किया गया कोई भी संव्यवहार पंजाब नेशनल बैंक की बकाया रूपये 42,47,087/- (रूपये बयालीस लाख सेतालीस हजार सतयासी रूपये मात्र) 13.02.2019 तक जिसके साथ भविष्य का ब्याज दिनांक 01.01.2019 से प्रभवी एंव कानूनी प्रभार और अन्य खर्चो सहित (सुरक्षीत ऋण के रूपमें जानने वाला)के लिये पंजाब नेशनल बैंक राशि के अध्याधीन होगा।

बंधक रखी गई सम्पत्ति के मोचन हेतु उपलब्ध समय के सम्बंध मे ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8)की व्यवस्थाओं की ओर दिलाया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

बंधक आई पी सम्पत्ति:- के-6, तीसरी मंजिल, नवीन शाहदरा दिल्ली-110092 में श्रीमती रवजीत के नाम से स्थित है।
दिनांक 08.11.2019 स्थान-नवीन शाहदरा प्राधिकृत अधिकारी (पंजाब नेशनल बैंक)

बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड
सीआईएन : L15421WB1975PLC030118
पंजी. कार्यालय : एफएमसी फॉर्च्यूना, द्वितीय तल,
234 / 3ए, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता–700020
फोन : +91 33 2287 4749, फैक्स : +91 33 2287 3083
ई–मेल आईडी : secretarial@bcml.in, वेबसाइट : www.chini.com

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर्स का विसूचीयन) विनियमावली, 2009, यथा संशोधित, ("विसूचीयन विनियमावली") के विनियम 6(क), 7 तथा अन्य लागू विनियमों, यदि कोई, के अनुसरण में बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड (कम्पनी) अपने इक्विटी शेयरों के दि कैलकटा स्टॉक एक्सचेन्ज लिमिटेड (सीएसई) से स्वैच्छिक विसूचीयन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है।

वर्तमान में कम्पनी के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड (बीएसई), नैशनल स्टॉक एक्सचेन्ज (एनएसई) तथा सीएसई में सूचीबद्ध हैं। कम्पनी के निदेशक मंडल ने सोमवार, 11 नवम्बर, 2019 को आयोजित इसकी बैठक में यह ध्यान में रखते हुए कि सीएसई में कम्पनी के इक्विटी शेयरों में कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, विसूचीयन विनियमावली के विनियम 6(क) के अनुसरण में, सीएसई से कम्पनी के इक्विटी शेयरों के स्वैच्छिक विसूचीयन का अनुमोदन किया है।

कम्पनी के इक्विटी शेयर बीएसई तथा एनएसई में सूचीबद्ध बने रहेंगे, जोकि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज हैं तथा राष्ट्र–व्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल्स के धारक हैं।

वास्ते बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड
हस्ता. / –
नितिन बाडड़िया
कम्पनी सेक्रेटरी – जीएम लीगल
एसीएस नंबर : 20228

स्थान : कोलकाता
तिथि : 11 नवम्बर, 2019

बीएस बातचीत

हमारा 20 प्रतिशत राजस्व डिजिटल से

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए टैरिफ ऑर्डर (एनटीओ) से वैल्यू चेन में पारदर्शिता बढ़ी है। प्रसारकों के लिए सदस्यता राजस्व बढ़ा है, भले ही ग्राहक संख्या में कमी आई है। वायकॉम18 के समूह सीईओ एवं प्रबंध निदेशक **सुधांशु वत्स** ने **सोहिनी दास** के साथ बातचीत में कंपनी की डिजिटल रणनीति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वह अगले पांच साल में वायाकॉम18 के राजस्व में डिजिटल का 20 प्रतिशत योगदान रहने की संभावना है। पेश हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश:

आपने वूट किड्स पेश किया है। भारत में किड्स एंटरटेनमेंट बाजार में किस तरह की संभावनाएं हैं?
बच्चों के लिए वीडियो उत्पाद उपलब्ध हैं। हमारा पहला उत्पाद है जिसमें हमने वीडियो, ई-बुक्स, ऑडियो-बुक्स और लाइट गेमिंग समेत कई पेशकशें की हैं। यह बेहद खास प्रोडक्ट है जिसमें बच्चों के लिए सुरक्षित परिवेश पर जोर दिया गया है। इसके लिए हमें टर्नर से कंटेंट मिला है। किड्स एंटरटेनमेंट उत्पादों पर प्रति परिवार औसत खर्च लगभग 12,000 से 14,000 रुपये सालाना है और यह तेजी से बढ़ रहा है। वूट किड्स सबस्क्रिप्शन मॉडल होगा और हम इसमें तीन राजस्व स्रोतों की संभावना तलाश रहे हैं। हम मौजूदा उपयोगकर्ताओं को इसकी बिक्री करने की कोशिश करेंगे, और फिर उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष विकल्प तलाशेंगे, और दूरसंचार या मूल उपकरण निर्माताओं के साथ भागीदारियों पर भी विचार करेंगे। वूट के अब 8 करोड़ मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। यह अभी तक विज्ञापन-केंद्रित मॉडल है और सदस्यता-मुक्त है।

डिजिटल प्लेटफॉर्मों की बिक्री पर आपका क्या नजरिया है?
मौजूदा समय में इंटरनेट सेवा बेहद किफायती हो गई है। ऐसे में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या तेज से बढ़ रही है। मौजूदा समय में लगभग 45 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। इनमें 35 करोड़ इंटरनेट वीडियो उपयोगकर्ता हैं। भारत इस संदर्भ में चीन की तरह विकास करना चाहेगा। 7-8 साल पहले चीन में लगभग 35-40 करोड़ इंटरनेट वीडियो उपयोगकर्ता थे, जो हमारे यहां मौजूदा संख्या के लगभग समान है। इनमें से ज्यादातर उपयोगकर्ता नि:शुल्क थे। वर्ष 2018 में चीन में 80 करोड़ इंटरनेट वीडियो उपयोगकर्ता थे और लगभग 15-20 प्रतिशत भुगतान वाले उपयोगकर्ता हैं।

मौजूदा समय में डिजिटल से राजस्व की भागीदारी कैसी है?
लगभग तीन साल पहले यह लगभग शून्य थी। मौजूदा समय में यह हमारे कुल राजस्व का लगभग 7 प्रतिशत है। पांच साल में हम अपने कुल राजस्व में डिजिटल की भागीदारी 20 प्रतिशत करने में कामयाब रह सकते हैं।

ट्राई के एनटीओ से परिदृश्य कितना बदला है?
हमें अन्य बदलावों की जरूरत नहीं है। भारत जैसे बड़े देश में इस तरह के किसी बदलाव के बाद पूरी तरह स्थिर होने में 6 महीने लगते हैं। लगभग 94 प्रतिशत भारतीय एनटीओ के बारे में अवगत हैं, जो एक अच्छी बात है। हमारे दो-तिहाई ग्राहकों ने डिस्ट्रीब्यूटर पैक को खरीदा है। वहीं हमारे एक-तिहाई ग्राहकों ने या तो माई पैक (कलर्स पैक) को सब्सक्राइब किया है या फिर वे अला-कार्टे चैनल ले रहे हैं।

क्या एनटीओ के बाद ग्राहक आधार में बदलाव आया है?
मौजूदा समय में हम बड़ा बदलाव देख रहे हैं, और यह बदलाव काफी हद तक उसी तरह का है जैसा कि दूरसंचार कंपनियों के मामले में है। हमारे पास बदलाव की धारणा कभी नहीं थी। एनटीओ के बाद, 7-8 प्रतिशत बदलाव हुआ है जो अब बरकरार है।

बोली शर्तों में संशोधन करेगी ओएनजीसी

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 12 नवंबर

- **उत्पादन बढ़ाने की योजना शर्तों में संशोधन करेगी ओएनजीसी**
- **कंपनी 64 तेल एवं गैस क्षेत्रों के लिए उत्पादन बढ़ाने की योजना शर्तों को संशोधित कर सकती है**
- **उद्योग सूत्रों ने कहा, संशोधित शर्तों को दोबारा कैबिनेट से मंजूरी की दरकार होगी**
- **बोली पूर्व बैठक में भाग लेने वाली 23 में से 14 कंपनियों ने परिचालन लागत से संबंधित मुद्दे पर सवाल उठाया था**
- **हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय और ओएनजीसी ने अब अनुबंध शर्तों में संशोधन करने का निर्णय लिया है**

तेल एवं गैस उत्खनन क्षेत्र की सरकारी कंपनी ओएनजीसी 64 तेल एवं गैस क्षेत्रों में उत्पादन बेहतर करने की बहुचर्चित योजना की शर्तों में संशोधित कर सकती है। संभावित बोलीदाताओं द्वारा परिचालन लागत एवं अन्य बोली मानदंडों पर चिंता जताए जाने के बाद कंपनी ने यह पहल की है।

विभिन्न सूत्रों के अनुसार, 17 सितंबर को बोली पूर्व बैठक में भाग लेने वाली 23 कंपनियों में से कम से कम 14 कंपनियों ने परिचालन लागत से संबंधित मुआवजे का वहन बुनियादी उत्पादन से संबंधित ठेकेदारों को करना चाहिए। उसके बाद हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) और ओएनजीसी ने अनुबंध शर्तों में संशोधन करने का निर्णय लिया इसी साल फरवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओएनजीसी और ऑयल इंडिया द्वारा खोजे गए 66 सीमांत तेल एवं गैस क्षेत्र निजी कंपनियों को आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

उद्योग सूत्रों ने कहा कि संशोधित शर्तों को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी की दरकार होगी। हालांकि एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'इस प्रक्रिया के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बोली प्रक्रिया की औपचारिकताओं को केवल ओएनजीसी और ऑयल इंडिया द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।'

बोली पूर्व बैठक में भाग लेने वाली कंपनियों में स्लमबर्गर, बेकर ह्यूजेस, वेदरफोर्ड इंटरनैशनल और हैलीबर्टन शामिल है। ओएनजीसी के चेयरमैन शशि शंकर ने कहा कि बोली प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर निदेशक मंडल पहले ही चिंता जता चुका है और अनुबंध शर्तों में संशोधन के बारे में अतिम निर्णय सरकार को लेना चाहिए।

ओएनजीसी के निदेशक (ऑनशोर) एसके मोइत्रा ने बोली पूर्व बैठक में निवेशकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर डीजीएच को 4 अक्टूबर को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि उनकी चिंता बुनियादी उत्पादन के लिए मुआवजा शुल्क को शामिल न किए जाने को लेकर थी और वे चाहते थे कि इस स्तर तक परिचालन बरकरार रखने के लिए परिचालन खर्च पर नए सिरे से मुआवजा दिया जाए। मौजूदा प्रावधानों के तहत ठेकेदार को केवल बढ़े हुए राजस्व में हिस्सेदारी का भुगतान करने की बात कही गई है।

ओएनजीसी ने 28 जून को बोली आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसमें सरकार द्वारा अधिसूचित 64 सीमांत क्षेत्र शामिल हैं जो 17 अनुबंध क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन क्षेत्रों में 30 करोड़ टन तेल समतुल्य गैस एवं तेल भंडार होने का अनुमान है।

आरंभिक चरण में बोली का आकलन करने वाली एक कंपनी के अधिकारी ने कहा, 'संभावित बोलीदाताओं अनुमानों से संबंधित एक प्रमुख मुद्दा उठाया था कि उस संबंध में किसी तीसरे पक्ष के आकलन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा राजस्व और जुर्माने से संबंधित मुद्दे भी थे क्योंकि इन क्षेत्रों में उत्पादन जारी है और हमारी जिम्मेदारी उत्पादन बढ़ाने की होगी।' बोली पूर्व बैठक से पहले प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर 21 संभावित बोलीदाताओं से ओएनजीसी को करीब 440 सवाल प्राप्त हुए थे।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
दिल्ली संस्करण

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, उ. प्र. से मुद्रित एवं नेहरु हाउस, 4 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित
संपादकः कैलाश नौटियाल

आरएनआई नo DELHIN/2008/27804
पाठक संपादक को **lettershindi@bsmail.in** पर संदेश भेज सकते हैं1
टेलीफोन- 011-23720202-10 फैक्स 011-23720201
सब्सक्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया सम्पर्क करें..
सुश्री मानसी सिंह
हेड कस्टमर रिलेशन्स
बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4 एवं आई/3, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013
ई मेल.. **subs_bs@bsmail.in**
या 57007 पर एसएमएस करें **SUB BS**

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है1 बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्‌भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए।
मै0 बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरु की जाएगी।
कोई हवाई अधिभार नहीं